IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 UDYAM-RJ-19-0033346 Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित मारवाड़ आंचल से प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 23 | अंक 14 | सांचौर, मंगलवार 15 जुलाई 2025 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

सहकारी बैंकों में सहकारी संस्थाओं के खाते व जमाएँ रखने की उठी मांग

जयपुर । वर्तमान में प्रदेश कें केंद्रीय सहकारी बैंकों में आर्थिक संसाधनों की स्थिती सुदृढ़ नहीं होने के कारण किसानों को राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत पर्याप्त सहकारी ऋण की सुविधा मिलने में परेशानी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के आर्थिक अनुशासन मानदण्डों की पालना करने सहित ऋण कारोबार से बैंक की लाभप्रदता को सुदृढ़ करने में भी परेशानी उत्पन्न हो रही हैं । वही रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान से पंजीकृत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के बैंक खाते एवं सावधि जमा के रूप में निवेश की जाने वाली धनराशि को अन्य बैंकों में रखी जा रही हैं । जिसे अब राज्य सहकारी बैंक और 29 केंद्रीय सहकारी बैंक में निवेश करवाने के लिए सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा हैं । जिसके मुताबिक, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारी संस्थाओं को आपसी संस्थागत कारोबारी सहयोग से आर्थिक समृद्ध बनाकर सहकारिता में सहकार से सहकारी समृद्धि को साकार करने का राष्ट्रीय संकल्प दिया गया, जिसके क्रम में सभी सहकारी संस्थाओं के बैंक खाते एवं सावधि जमाओं के साथ-साथ संस्थाओं व सहकारी विभाग कार्मिकों के वेतन खाते राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं 29 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में संधारण करवाने की मांग उठाई हैं ।

75.52 लाख किसानों को 42 हजार 131 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित

'सहकार से समृद्धि' की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार कर रही कार्य

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता के महत्व के दृष्टिगत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। राज्य सरकार 'सहकार से समृद्धि' की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य में नई सरकार के गठन से लेकर 30 जून, 2025 तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 75.52 लाख किसानों को लगभग 42 हजार 131 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जाने का राज्य बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उक्त अवधि में 805 करोड़ रुपये से अधिक के मध्यकालीन ऋण वितरित किये गए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा इस दौरान लगभग 232 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया

सहकारिता विभाग की योजनाओं का वृहद् स्तर पर आमजन को मिल रहा लाभ

वितरित किये गए हैं। इसी प्रकार, राज्य में नवीन सहकारी समितियों का गठन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जून, 2025 तक 216 नये पैक्स, 97 नये लैम्प्स और 313 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। राज्य बजट 2025-26 में आगामी दो वर्षों में शेष रही समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए समिति गठन के प्रावधानों में शिथिलता दी गई है। उक्त अवधि के दौरान 412 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। वहीं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 212 नये गोदामों का निर्माण किया गया है। इस अवधि में नये गोदामों के निर्माण पर लगभग 28 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। राज्य सरकार ने विभिन्न नई योजनाएं लागू कर किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बजट वर्ष 2024-25 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 6000 रुपये के अतिरिक्त 2000 रुपये दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रावधान किया। योजना के तहत 30 जून, 2024 को 65 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये प्रति कृषक के अनुसार कुल 653 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। योजना की दूसरी और तीसरी किश्त 70.21 लाख किसानों को

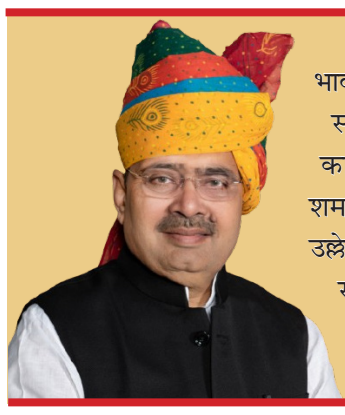

राज्य सरकार 'सहकार से समृद्धि' की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न नई योजनाएं लागू कर किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

1000 रुपये प्रति कृषक के अनुसार कुल 702.18 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वार्षिक वित्तीय सहायता राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी है। इसी प्रकार, डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे- गौवंश के लिए शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध/चारा/बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई। सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 शुरू की है। योजना के अंतर्गत मूलधन जमा करवाने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। समस्त ब्याज राशि और वसूली खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। योजना में 30 जून तक 4,88 2 ऋणियों को 81 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की गई है एवं 2,544 ऋणियों से 13.8 3 करोड़ रुपये की आंशिक वसूली प्राप्त की गई है।

सहकारिता विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धियां

- सरकार के गठन से लेकर 30 जून, 2025 तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 75.52 लाख किसानों को लगभग 42 हजार 131 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित
- वर्ष 2025-26 में 35 लाख कृषकों को 25 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरित करने बजट प्रावधान
- केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 805 करोड़ रुपये से अधिक के मध्यकालीन ऋण वितरित
- राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा 232 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित
- प्रदेश में जून 2025 तक 216 नये पैक्स, 97 नये लैप्स और 313 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन
- 412 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना
- ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 212 नये गोदामों का निर्माण
- मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वार्षिक वित्तीय सहायता राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 की
- 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू
- सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को राहत देने के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

संभाग स्तर पर सहकार मेलो का किया जाएगा आयोजन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

राजस्थान में इस वर्ष पहली बार जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में संभाग स्तर पर सहकार मेलों का किया जाएगा आयोजन

जयपुर । प्रदेश में पहली बार संभाग स्तर पर सहकार मेलों के आयोजन को लेकर सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय द्वारा अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड को पत्र जारी किया गया हैं । जिसके मुताबिक सहकारिता विभाग द्वारा अब संभाग स्तर पर तीन दिवसीय सहकार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जोधपुर संभाग में 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक सहकार मेला इसी प्रकार कोटा संभाग में 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक और उदयपुर संभाग में 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक सहकार मेला आयोजित होगा । साथ ही, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर संभाग में आयोजित होने वाले सहकार मेलों में संबंधित संभाग के सभी जिलों की सहकारी समितियां यथा जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां एवं मसाला उत्पादक महिला सहकारी समितियां एवं राजीविका के स्वयं सहायता समूहों द्वारा भाग लेने के साथ, मेले में क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध मसालों, श्री अन्न उत्पाद एवं एक जिला एक उत्पाद एवं भौगोलिक संकेतक उत्पाद एवं सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए उपलब्ध होगे । इसके अलावा, संबंधित संभाग में कार्यरत एफपीओ के उत्पाद भी बिक्री व प्रदर्शित किए जाएंगे । वही मेले के सफल आयोजन के लिए संभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड को मेला संयोजक और भण्डार महा प्रबंधक को मेला सचिव बनाया गया हैं ।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का जयपुर दौरा प्रस्तावित

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने की तैयारियों की समीक्षा कर तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करने के दिए निर्देश

सहकारिता मंत्री ने सहकार एवं रोजगार उत्सव की तैयारियों समयबद्ध रूप से पूरी करने के दिए निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में 17 जुलाई को जयपुर के दादिया ग्राम में प्रस्तावित सहकार एवं रोजगार उत्सव के मध्यनजर सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने अपेक्स बैंक सभागार में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं। श्री दक ने कहा कि श्री अमित शाह का यह दौरा सहकारिता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सहकारिता की दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। दौरे को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में प्रत्येक जिले एवं प्रत्येक सहकारी संस्था से प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। सभी आगन्तुकों के नाम एवं फोन नम्बर प्रभारी अधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही, रूट चार्ट, आगन्तुकों की सूची एवं चेक प्वाइंट्स आदि की जानकारी भी साझा कर ली जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में उनकी सुविधाओं का पूरा

सहकारिता मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और जो भी व्यक्ति कार्यक्रम में आए, यहां से अच्छी यादें लेकर जाए।

ध्यान रखा जाए। किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और जो भी व्यक्ति कार्यक्रम में आए, यहां से अच्छी यादें लेकर जाए। श्री दक ने आगन्तुकों के लिए भोजन, पेयजल एवं ठहरने आदि के समुचित बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर आगन्तुकों के लिए छाछ एव चाय की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती शिल्पी पांडे, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री संजय पाठक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) श्री संदीप खण्डेलवाल सहित कार्यक्रम के संबंध में गठित कमेटियों के प्रभारी अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम स्थल पर हैल्प डेस्क एवं कंट्रोल रूम स्थापित

सहकारिता मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर हैल्प डेस्क एवं कंट्रोल रूम स्थापित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हैल्प डेस्क और कंट्रोल रूम से जरूरतमंद को तत्काल सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कंट्रोल रूम की स्थापना कर खण्डवार 7 प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। श्री दक ने कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं लोगों को परेशानी से बचाने के लिए संकेत पट्ट लगाने के भी निर्देश दिए। श्री दक ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई जाने वाली प्रदर्शनी को भी समुचित रूप से आयोजित करने एवं आकर्षक बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें जो भी उत्पाद हाईलाइट किए जाने हैं, वे स्पष्ट हों। उन्होंने कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आगन्तुकों को राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित साहित्य वितरण के भी निर्देश दिए।

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से काश्तकारों का जीवन सँवारने में प्रदेश सरकार की अभिनव पहल

40 हजार पात्र गोपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में मिला 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान के समग्र विकास और जन-जन के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अनवरत भरसक प्रयासों के साथ प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार द्वारा कृषि और पशुपालन सहित सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पशुपालकों एवं किसानों की माली हालत सुधारने और इस क्षेत्र से जुड़े काश्तकारों को खुशहाल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों के घर-परिवार को समृद्धि की दिशा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाएं है । वही प्रदेश के किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ''राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना'' का सूत्रपात एक साल पूर्व राज्य सरकार द्वारा किया गया, इसमें डेयरी से सम्बन्धित गतिविधियों में सम्बल के लिए गोवंश हेतु शैड़, खेली का निर्माण तथा दुग्ध, चारा, बाटा सम्बन्धित उपकरण खरीदने हेतु एक लाख रुपए तक की धनराशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के कार्य किया जा रहा हैं । जिससे कृषि उत्पादकता और आय में सुधार हो रहा हैं ।

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवारों को एक लाख रुपये तक अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य बजट 2024-25 में प्रदेश के पांच लाख गोपालक परिवारों को इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया। अब राज्य बजट 2025-26 में इसमें 2 लाख 50 हजार अतिरिक्त गोपालक परिवारों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही, इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए वर्ष 2024-25 में एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और लगभग 40 हजार से अधिक परिवारों को करीब 270 करोड़ की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया।

खेती-बाड़ी और पशुपालन क्षेत्र में आ रहा आर्थिक सबल

गोवंश के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण पहल

योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के गोपालक किसान का प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। ऋण का समय पर चुकारा करने पर गोपालक किसानों को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता। योजना का लाभ उठाने के लिए गोपालक किसान ई-मित्र केन्द्र एवं संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से लाभान्वित होकर गोपालक परिवार अधिक मात्रा में शुद्ध दूध का उत्पादन कर पा रहे हैं और अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। साथ ही, यह योजना प्रदेश में गोवंश के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।

सहकार उत्सव से उत्साहित हैं राजस्थान की पैक्स और सीसीबी

राजस्थान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में होने वाले सहकार एवं रोजगार उत्सव से प्रदेश की पैक्स और सीसीबी अपने सुनहरे भविष्य की टकटकी लगाए बैठी हैं । विकसित भारत 2047 के निर्माण में केंद्रीय सहकारिता मंत्री का 'सहकार से समृद्धि' का विजन राज्य की पैक्स के लिए नया सवेरा तथा 'सहकारिता में सहकार' का वाक्य केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए आशा की किरण लेकर आया हैं । राज्य में पैक्स और सीसीबी में असीम क्षमताएं हैं। जरूरत है उन्हें सही दिशा देने और उनकी क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग करने की। इन संस्थाओं की इस असीमित क्षमता का इस्तेमाल कर ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से जुड़ी पैक्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सहकारिता क्षेत्र का प्रभाव देशभर में व्यापक रूप से बढ़ रहा है। खासकर केंद्रीय स्तर पर जब से अलग सहकारिता मंत्रालय बना है, तब से इस क्षेत्र में व्यापक सुधार के कई कदम उठाए गए हैं जिससे भारत में सहकारिता आंदोलन मजबूत हो रहा है। अब राजस्थान में देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाले विशाल सहकार उत्सव के दौरान सहकारिता विभाग की झोली में क्या आएगा ? यह तो पता नहीं हैं ? लेकिन एक अनुमान के अनुसार, इस विशाल सहकार उत्सव आयोजन के लिए कंगाली के दौर में गुजर रही केंद्रीय सहकारी बैंकों से भारी-भरकम राशि खर्च होना तय हैं । अब इतनी राशि खर्च करने में रजामंद सीसीबी, अपने राज्य सरकार स्तर से कर्ज माफी के विलंब भुगतान में देय ब्याज के तौर पर बकाया 767 करोड़ की राशि के साथ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन फसली ऋण पेटे मिलने वाले 12 प्रतिशत पुनर्वित्त के स्थान पर पुनः 40 प्रतिशत पुनर्वित्त नाबार्ड से मिलने जैसे घोषणा की प्रतीक्षा कर रही हैं । इतना ही नहीं, सीसीबी के साथ लगे हाथ प्रदेश की पैक्स भी अपनी व्यथा दूर होने की आस में सहकार उत्सव को सफल बनाने के लिए कदम ताल से कदम ताल मिला रही हैं । क्योकि प्रदेश की 2000 से ज्यादा पैक्स घटते ऋण व्यवसाय के चलते असंतुलन की ओट में समा गई हैं और तो और 3000 पैक्स मानव संसाधनों की कमी के बावजूद विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इसी आस में प्रयासरत हैं कि एक दिन विकसित भारत निर्माण के साथ विकसित पैक्स निर्माण का भी इस प्रदेश में विजन आएगा । अब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन मे भारत सरकार सहकारी आंदोलन को निरंतर गति, विस्तार एवं दिशा दे रहा है। तो क्या अमित शाह इस विशाल सहकार उत्सव में पैक्स और सीसीबी *(जो अपनी वाजिब मांगों के लिए लंबे समय से संघर्षरत रही)* की आवाज सुन पाएंगे ? या फिर यह आशा की किरण हमेशा की तरह इस बार भी धूमिल होकर कर रह जाएगी ?

सहकारिता से आदर्श समाज का निर्माण

ललित गर्ग
(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)
(यह लेखक के अपने विचार है)

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों को रेखांकित करने और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को सम्मानित करने का अवसर होता है। सहकारिता एक ऐसा आंदोलन है जो 'एकता में शक्ति' की भावना को मजबूत करता है और लोकतांत्रिक, समावेशी और न्यायसंगत आदर्श समाज के निर्माण में सहायक बनता है। सहयोग की शक्ति और सामाजिक समरसता के इस उत्सव का 2025 की थीम है 'सहकारिताः एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना।' यह थीम पर्यावरण-संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, और सामाजिक समावेशन जैसे विषयों को सहयोग के माध्यम से हल करने की प्रेरणा देती है। आज के समय में जब आर्थिक विषमता और सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है, सहकारिता एक वैकल्पिक और मानवीय मॉडल प्रस्तुत करती है। यह न केवल आर्थिक विकास की राह दिखाती है, बल्कि सामाजिक विश्वास, सह-अस्तित्व और भाईचारे को भी बढ़ावा देती है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह 29वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस और 104वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस होगा। यह सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के पूरक लक्ष्यों और उद्देश्यों को उजागर करना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में आंदोलन के योगदान को रेखांकित और विस्तारित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा 2012 में पहले सफल आयोजन के बाद की गई है और वैश्विक स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। दुनिया भर की सहकारी समितियां दिखाएंगी कि कैसे वे एकजुटता और लचीलेपन के साथ युद्ध, महामारी एवं प्राकृतिक आपदा संकट का सामना कर रही हैं और समुदायों को जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से न्यायसंगत पुनर्प्राप्ति की पेशकश कर रही हैं। सहकारिता दिवस इस बात का प्रचार करने का अवसर है कि किस प्रकार मानव-केन्द्रित व्यवसाय मॉडल, जो स्वयं-सहायता और एकजुटता के सहकारी मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व और समुदाय के प्रति चिंता के नैतिक मूल्यों द्वारा समर्थित है, असमानता को कम कर सकता है, साझा समृद्धि का सृजन कर सकता है। सहकारी समितियां, जो आर्थिक सफलता को सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव सदस्य देशों को सहकारी समितियों के लिए एक सहायक कानूनी और नीतिगत माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें कृषि, वित्त और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्व पर जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया है। आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को ने इस घोषणा को संगठन के सतत विकास के लिए चल रहे प्रयासों के साथ सरेखित करने पर प्रकाश डाला। इस घोषणा से वैश्विक स्तर पर समानतापूर्ण और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी समितियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है, खासकर जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने। सहकारिता पर ध्यान केंद्रित करके, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य टिकाऊ, समुदाय-केंद्रित समाधान प्रदान करने में मॉडल की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है। सहकारिता, जिसे अंग्रेजी में कोआपरेटिव कहते हैं, एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग स्वेच्छा से मिलकर काम करते हैं ताकि अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह एक लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित व्यवसाय है जहां सदस्य ही मालिक होते हैं और व्यवसाय का संचालन और लाभ का वितरण भी सदस्यों के बीच ही होता है। सहकारिता का अर्थ है, 'मिलजुल कर काम करना' या 'आपस में सहयोग करना'। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग स्वेच्छा से एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि वे अपने सामान्य आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें. सहकारिता का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग, समानता और सामूहिक हित को बढ़ावा देना है। इसका मूल मंत्र है 'सभी के लिए एक, और एक सभी के लिए।' भारत में सहकारिता की भावना एवं विचारधारा आजादी से पहले से जन-जन में रची-बसी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुली मिली है, ये कोई उधार लिया विचार नहीं है। सहकारिता भारत के संस्कार में है। भारत में सहकारिता आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। सहकारिता की जड़े 1904 के सहकारी ऋण समितियां अधिनियम से जुड़ी हैं। स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन और भी सशक्त हुआ। चाहे अमूल जैसी डेयरी सहकारी संस्थाएं हों या सहकारी बैंकों और किसान समितियां, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब सहकारिता आंदोलन की सबसे अधिक जरूरत थी, तब यशस्वी एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन करके सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को नये आयाम दिये हैं। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री अपने-अपने राज्यों में कृषि मंत्रियों के साथ समन्वय कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आम लोगों के साथ-साथ धरती माता का स्वास्थ्य भी बेहतर हो सके। गरीब कल्याण और गरीब उत्थान, बिना सहकारिता के सोचा नहीं जा सकता। नरेन्द्र मोदी के मन की इच्छा है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, सहकारिता की प्रक्रिया से हर घर को समृद्ध बनाना और हर परिवार की समृद्धि से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकार से समृद्धि का मंत्र है। देश पर जब-जब कोई विपदा आई है, सहकारिता आंदोलनों ने देश को बाहर निकाला है। कॉपरेटिव बैंक बिना मुनाफे की चिंता किए लोगों के लिए काम करते हैं क्योंकि, भारत के संस्कारों में सहकारिता है। आज देश में लगभग 91 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां छोटी-बड़ी कोई न कोई सहकारी संस्था काम करती है। सहकारिता गरीबों और पिछड़ों के विकास के लिए है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-(एनसीडीसी) और सहकारिता मंत्रालय जैसे संस्थान इस क्षेत्र को संगठित और सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की सहकारिता सोच एवं मोदी सरकार की प्रतिबद्धताएं दुनिया के लिये एक प्रेरक मॉडल है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक ऐसा आंदोलन जो समाज को जोड़ने, ऊपर उठाने, संतुलित विकास और ग्रामीण जीवन को टिकाऊ बनाने की क्षमता रखता है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि यदि हम साथ मिलकर कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सहयोग ही सशक्तिकरण की कुंजी है।

> **"भारत की सहकारिता सोच एवं मोदी सरकार की प्रतिबद्धताएं दुनिया के लिये एक प्रेरक मॉडल है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक ऐसा आंदोलन जो समाज को जोड़ने, ऊपर उठाने, संतुलित विकास और ग्रामीण जीवन को टिकाऊ बनाने की क्षमता रखता है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि यदि हम साथ मिलकर कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सहयोग ही सशक्तिकरण की कुंजी है।"**

प्रदर्शनी में दिखाई गई सहकारी आन्दोलन की यात्रा, सहकारी संस्थाओं द्वारा स्टॉल्स पर उत्पाद भी किये गए प्रदर्शित

नेहरू सहकार भवन में लगी 'सहकारिता का सफरः अतीत से वर्तमान तक' विषय पर प्रदर्शनी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । नेहरू सहकार भवन में 'सहकारिता का सफर अतीत से वर्तमान तक' विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने फीता काटकर एवं गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारभ किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदर्शित की गई जानकारी की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (5 जुलाई) एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के चतुर्थ स्थापना दिवस (6 जुलाई) के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही गतिविधियों की श्रंखला में प्रचार अनुभाग द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में सहकारी आन्दोलन के अब तक के सफर को आकर्षक रुप में विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन भारतीय लोकाचार में सहकारिता के बीज, विश्व में सहकारी आन्दोलन का शुभारभ, भारत में सहकारी आन्दोलन का शुभारभ, राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का शुभारभ, राजस्थान में सहकारी विधि का विकास, राज्य में सहकारिता की त्रिस्तरीय संरचना, राज्य में शीर्ष सहकारी संस्थाओं का इतिहास एवं वर्तमान स्वरूप आदि से सबन्धित जानकारियों के साथ ही सहकारिता के सिद्धांत एवं उद्देश्य, सहकार से समृद्धि के अंतर्गत राज्य की प्रमुख उपलब्धियां, राज्य में सहकारिता का वर्तमान परिदृश्य एवं वर्तमान में सहकारिता की प्रासंगिकता आदि से संबंधित जानकारियां प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। वहीं, राज्य में सहकारी आन्दोलन के विकास के जुड़े पुराने छायाचित्रों को भी प्रदर्शनी में आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में विभिन्न सहकारी संस्थाओं कॉनफेड, ट्राइफेड, इफको, कृभको एवं तिलम संघ द्वारा भी स्टॉल्स लगाकर अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। श्रीमती राजपाल ने इन स्टॉल्स का अवलोकन कर प्रदर्शित उत्पादों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण कर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया। इस दौरान सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सहकारिता का सफर अतीत से वर्तमान तक' विषय पर प्रदर्शनी

प्राचीन भारतीय लोकाचार में सहकारिता के बीज, विश्व में सहकारी आन्दोलन का शुभारभ, भारत में सहकारी आन्दोलन का शुभारभ, राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का शुभारभ, राजस्थान में सहकारी विधि का विकास, राज्य में सहकारिता की त्रिस्तरीय संरचना, राज्य में शीर्ष सहकारी संस्थाओं का इतिहास एवं वर्तमान स्वरूप आदि से सबन्धित जानकारियों के साथ ही सहकारिता के सिद्धांत एवं उद्देश्य, सहकार से समृद्धि के अंतर्गत राज्य की प्रमुख उपलब्धियां, राज्य में सहकारिता का वर्तमान परिदृश्य एवं वर्तमान में सहकारिता की प्रासंगिकता आदि से संबंधित जानकारियां प्रदर्शनी में प्रदर्शित

केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारी सरकार से नाराज, दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतवानी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के लिए आंदोलन पर उतारू हैं । इसके लिए 14 जुलाई को सहकारी बैंकों की 18 जिला यूनिटों द्वारा सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया । साथ ही, इससे पूर्व 7 व 8 जुलाई को बैंक कर्मियों द्वारा काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया था । अब 17 जुलाई को भी एक दिवसीय हड़ताल का, पूर्व में बैंक प्रबंधन और सहकारिता विभाग को नोटिस दिया हुआ हैं । वही इसी ही दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजस्थान में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होने जा रहा हैं । इसी कार्यक्रम को देखते हुए ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन यूनिट श्रीगंगानगर के अध्यक्ष राजेश शर्मा एवं ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव महेश सिरोही ने अपनी लंबित मांगों के संबंध में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को भी जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन भेजा हैं । वही ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक यूनियन एवं ऑफिसर एसोसिएशन के जिला यूनिट पदाधिकारियों का कहना हैं कि बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को प्रबंधन के समक्ष रखते रहे हैं लेकिन, कर्मचारियों की बेसिक मांग भी पूरी नहीं की जा रही हैं । उन्होंने कहा कि राजस्थान में 18 जिलों यूनिट ने सहकारिता विभाग के नाम 16 सूत्री मांग पत्र दिया हैं, जिस पर 20 जुलाई तक सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिती में 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की जाएगी । साथ ही, इनका कहना हैं कि प्रमुख मांगो में ऋण माफी के विलंब भुगतान पेटे बकाया राशि सरकार से जल्द जारी करवाने तथा कर्मचारियों की लंबित डीपीसी, नाबार्ड द्वारा साख नीति समय पर जारी करने की मांगों को लेकर गत कई दिनों से कार्मिक आंदोलन की राह पर है।

बाड़मेर सीसीबी प्रधान कार्यालय के आगे सांकेतिक धरना

चूरू में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सीसीबी कर्मचारी

श्रीगंगानगर में बारिश के दौरान भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते सीसीबी कर्मचारी

यूनियन यूनिटों की ये है प्रमुख मांग

- सरकार स्तर पर सीसीबी के ऋण माफी पेटे बकाया 765 करोड़ का हो भुगतान
- अल्पकालीन फसली ऋण के लिए नाबार्ड से अप्रैल माह में जारी की जाएं ऋण नीति
- फसली ऋण पेटे सहकारी बैंकों को किया जाएं 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का भुगतान
- केंद्रीय सहकारी बैंकों का किया जाएं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में विलयकरण
- केंद्रीय सहकारी बैंकों में अन्तर जिला स्थानान्तरण नीति हो लागू
- शीर्ष सहकारी बैंक में ऋण अनुपात से अधिक जमा राशि का हो समायोजन
- 17वां वेतन समझौता लागू करने के लिए हो कमेटी गठित
- सीसीबी में स्टाफ स्ट्रैथ के लिए नाबार्ड की अमलोरपवनाथन कमेटी की सिफारिश हो लागू
- नागौर, पाली और जैसलमेर सीसीबी में हो 16वां वेतन समझौता लागू
- सीसीबी से ऋण लेने वाले किसानों की जमीन कुर्की पर लगाई हुई रोक हटाएं

मौन और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन एवं ऑफिसर एसोसिएशन की जिलों यूनिटों द्वारा दिए गए ज्ञापन के मुताबिक, 14 जुलाई को बैंक कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन और 17 जुलाई को हड़ताल एवं सद्बुद्धी यज्ञ किया जाएगा । इसके बाद भी सरकार एवं सहकारिता विभाग द्वारा यूनियन की 16 सूत्रीय मांगपत्र पर कोई संज्ञान या निर्णय नहीं लिया जाता हैं, तो मजबूरन 21 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की जाएगी ।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/-☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details : Name: Marwad ka Mitra A/C No.: 11134027554 IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

1,08,000 पैक्स को बनाया जाएगा डिजिटल : सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड और पीएचडीसीसीआई का संयुक्त प्रयास

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली स्थित पीएचडी हाउस में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और पीएचडीसीसीआई के संयुक्त तत्वावधान में पैक्स में उभरती प्रौद्योगिकियां विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत देशभर में सहकारी विकास को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सम्मेलन में 12 राज्यों के 122 से अधिक पैक्स प्रतिनिधियों सहित नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स और राष्ट्रीय संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि देश में 1,08,000 से अधिक पैक्स वर्तमान में 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण सदस्यों को ऋण वितरित कर रही हैं। अब समय आ गया है कि इन संस्थाओं को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार किया जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स को व्यावसायिक और बहुउद्देशीय आर्थिक इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए मंत्रालय व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दे रहा है। सम्मेलन के अंत में तैयार की गई सिफारिशों की रिपोर्ट को सहकारिता मंत्रालय एवं विभिन्न राज्य सरकारों को नीति निर्माण और बजटीय मार्गदर्शन के लिए सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, विभिन्न राज्यों के सहकारिता सचिव, एनसीडीसी, एनईएफईडी, एनडीडीबी, एनएफडीबी के अधिकारी, प्रमुख एग्रीटेक कंपनियां और स्टार्टअप्स के लोग मौजूद रहे।

पीएचडीसीसीआई और नाबार्ड का सहयोग

कार्यक्रम को पीएचडीसीसीआई के महासचिव डॉ. रणजीत मेहता ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत यह सम्मेलन डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त कदम है। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत ने अपने संबोधन में बताया कि नाबार्ड पैक्स को कंप्यूटरीकरण, वित्तीय सहायता, नीति मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत करेगा।

महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा

कार्यक्रम में पैक्स ईआरपी प्रणाली का लाइव डेमो किया गया। जनरेटिव एआई टूल के उपयोग पर विचार विमर्श के साथ डिजिटल युग में पैक्स की भूमिका पर पैनल चर्चा की गई। राज्य स्तर पर डिजिटलीकरण के सफल केस स्टडी और प्रशिक्षण, सतत नवाचार के लिए रोडमैप तैयार किया गया। सम्मेलन में एआई, कोर बैंकिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को पैक्स के दैनिक संचालन में एकीकृत करने पर विशेष बल दिया गया।

सहकारी बैंकों को पर्याप्त पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाएं नाबार्ड - आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के निर्माण में सहकारिता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता से समृद्धि और सहकारिता में सहकार का ध्येय वाक्य दिया हैं, जिसमें नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती हैं । ऐसा सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस पर सहकार जनों को बधाई देते हुए कहा हैं । दरअसल, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना देश में किसानों को पैक्स एवं सहकारी बैंक के माध्यम से सहकारी फसली ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के प्राथमिक उद्देशय के साथ 12 जुलाई 1982 को हुई, जिसकी याद दिलाते हुए सहकार नेता आमेरा ने नाबार्ड से सहकारी बैंकों को समुचित फसली ऋण पुनर्वित्त सुविधा करवाने मांग दोहराते हुए कहा हैं कि देश में अल्पकालीन व दीर्घकालीन सहकारी साख आंदोलन की स्थिति पर नाबार्ड टीम अपने स्थापना दिवस पर उद्देश्यों प्राप्ति की समीक्षा करने की बात रखी हैं । क्योकि आज कई राज्यों में सहकारी भूमि विकास बैंक बंद होकर रह गए हैं और अधिकांश राज्यों में पैक्स व सीसीबी की स्थिति आशानुकूल नहीं के बराबर होकर रह गई हैं । इसके अलावा, आमेरा ने अल्पकालीन फसली ऋण की पॉलिसी विलंब घोषणा के बजाए फसल चक्र के समय ही घोषणा करने के साथ सहकारी बैंकों को 12 प्रतिशत पुनर्वित्त की जगह पूर्ववृत्त की तरह 40 प्रतिशत पुनर्वित्त सुविधा देने की मांग भी उठाई हैं ।

रियायाती ब्याज दर पर पुनर्वित्त

सहकार नेता आमेरा ने शीर्ष सहकारी बैंक को इकोनॉमिक लैंडिंग के नाम पर उच्च ब्याज दर पर पुनर्वित्त की स्थान पर रियायती दर पर अधिकाधिक पुनर्वित्त उपलब्ध कराने की मांग नाबार्ड से करते हुए कहा हैं कि सहकारी बैंकों में योग्य उचित प्रबंधकीय व्यवस्था व आर्थिक पारदर्शिता के लिए नाबार्ड को रिजर्व बैंक की अपेक्षानुरूप अपनी निरीक्षण जिम्मेदारी को प्रभावी करने की जरूरत हैं । क्योकि सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता व प्रशासकीय कुशलता नाबार्ड निरीक्षण की मुख्य जिम्मेदारी है ।

सम्मानित होने वालो को दी बधाई

राजस्थान में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापना दिवस के उपलक्ष में कार्यक्रम में आयोजित किया गया । जिसमें प्रदेश की कोटा, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर सीसीबी के साथ श्रीगंगानगर जिले की घमुड़वाली पदमपुर, कोटा जिले की बोरखेड़ा और नागौर जिले की निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति को सहकारिता क्षेत्र में सराहनीय सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया । जिसके उपरांत आज सहकार नेता ने सम्मानित होने वाली सीसीबी और पैक्स को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारियों एवं कार्मिकों सहित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों और निर्वाचित संचालक बोर्ड सदस्यों को इनसें प्रेरणा लेनी चाहिए ।

बिहार के सहकारिता मंत्री ने उदयपुर सीसीबी का किया अवलोकन

उदयपुर । जिले के प्रतापनगर स्थित उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय का बिहार राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने अवलोकन किया । साथ ही, उदयपुर सीसीबी में बनी सहकार गैलेरी के अन्तर्गत बैंक के स्थापना वर्ष 1956 से लेकर वर्तमान समय तक हुए आयोजनों एवं मुख्य योजनाओं का जिनका प्रदर्शन तस्वीरो, बैनर, पोस्टर एवं स्टैण्डी के माध्यम से किया गया था, का रुचिपूर्वक अवलोकन करते हुये सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बैक की प्रगति की सराहना की । सीसीबी प्रबंध निदेशक डॉ. मेहजबीन बानो ने वर्तमान में सहकार से समृद्धि के अंतर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्यकलापो से सहकारिता मंत्री को अवगत कराया । जिसके पश्चात केंद्रीय सहकारी बैंक एवं विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार से सहकारिता विभाग संयुक्त निबधंक सहयोग समितियां समरेश कुमार, वरीय सहाकरिता प्रसार पदाधिकारी आनन्द कुमार, विनय जैन, निजी सहायक शेखर सुमन एवं सहयोगी अनिल कुमार ने भाग लिया ।

पात्र ऋणियों द्वारा 30 सितबर तक जमा करवाई जा सकेगी 25 प्रतिशत राशि

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की बढ़ाई अवधि

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी सदस्यों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि बढ़ा दी है। योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी अब अपने हिस्से की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि 30 सितम्बर, 2025 तक जमा करवा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि योजना को लेकर ऋणी सदस्यों में काफी उत्साह है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से आकर्षित होकर अवधिपार खातों के निस्तारण हेतु प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना के अंतिम दिन 30 जून को भारी भीड़ उमड़ी और पोर्टल पर रसीदें कटवाने के लिए देर रात्रि तक कतारें लगी रहीं। इसके बावजूद कई ऋणी सदस्य योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। योजना के लाभ से वंचित रहे ऐसे ऋणी सदस्यों की ओर से लगातार आ रही मांग के आधार पर राज्य सरकार ने अन्तिम तिथी को बढ़ाकर 30 सितम्बर 2025 तक करने का अहम निर्णय लिया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की किसान हित में लागू इस योजना से लाभान्वित ऋणी सदस्यों को पुन: मुख्यधारा में लाए जाने के लिए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में दीर्घकालीन कृषि व अकृषि निवेश ऋण भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के 36 प्राथमिक बैंकों को ऋण वितरण लक्ष्य आवंटित किए गए है।

राज्य सरकार द्वारा 7,500 से अधिक ऋणी सदस्यों का वहन किया गया 130 करोड़ रुपये का ब्याज

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत कुल 30,007 पात्र ऋणियों में से अब तक 7,500 से अधिक ऋणी सदस्यों को लगभग 130 करोड़ रुपये का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाकर राहत से लाभान्वित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ऋणी किसान भूमि विकास बैंकों के पास रहन रखी अपनी भूमि को मुक्त करवा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गई इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत ऋणियों को अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में शत प्रतिशत राहत दिए जाने का प्रावधान है। पात्र ऋणियों द्वारा केवल मूलधन एवं बीमा प्रीमियम की राशि चुकाई जानी है।

राजेफड और राष्ट्रीय स्तर पर गठित बहुराज्यीय सहकारी समितियों के मध्य एमओयू से किसानों को मिलेगा लाभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारी समितियों व किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाये जाने तथा जैविक उत्पादों के विपणन हेतु राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ (राजफेड) द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लि. एवं राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. के साथ एमओयू किया गया है। बुधवार को राजफेड कार्यालय में एमओयू की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इन एमओयू का लाभ आगामी दिनों में किसानों एवं सहकारी समितियों से जुड़े सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर मिलेगा। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक के नेतृत्व तथा सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल के निर्देशन में राज्य में 'सहकार से समृद्धि' की पहल को बेहतर रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। श्री दक एवं श्रीमती राजपाल की मंशा के अनुरूप हुए इन एमओयू से सहकारिता के क्षेत्र में जैविक उत्पादों के विपणन, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज एवं आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने तथा बाजार तक कृषक समूहों की पहुंच बढ़ाने में सहायता मिलेगी। एनसीओएल के साथ एमओयू से बासमती चावल, धान, गेहूं, दालें, शहद, मिलेट्स एवं औषधीय उत्पादों आदि के लिए विपणन के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। राजफेड की ओर से प्रबंध संचालक श्री टीकम चन्द बोहरा ने करार पर हस्ताक्षर किये जबकि, भारतीय बीज सहकारी समिति लि. की ओर से इंस्टीट्यूशनल हैड श्री परमवीर यादव एवं राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. की ओर से को-ऑपरेटिव हैड श्री विनीत कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्रीमान, सुभाष चंद्र आर्य

मुख्य शिल्पी निमोद प्राथमिक बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति को सराहनीय प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के 44वें स्थापना दिवस पर नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजीव सिवाच और महाप्रबंधक श्रीमती मंजू खुराना सहित राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक संजय पाठक द्वारा पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

शुभेच्छु

खेमाराम बुगालिया अध्यक्ष, झुमरलाल व्यवस्थापक
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण व समस्त सोसाइटी कर्मचारी गण
निमोद प्राथमिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड निमोद
पंचायत समिति - डीडवाना, जिला - डीडवाना-कुचामन

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

सांचौर (जिला-जालोर) मंगलवार, 15 जुलाई 2025

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136

Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस विशेष

सरकार के निर्णयों से 'सहकार से समृद्धि' के पथ पर आगे बढ़ रहा राजस्थान

- राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का लगभग 125 वर्षों का गौरवशाली इतिहास
- 60 से अधिक पहलों के माध्यम से सहकारी सेक्टर को बनाया जा रहा सशक्त
- सहकारिता के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया

- विशेष रूप से किसानों, श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु व्यवसाईयों एवं विविध स्तरों पर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न जनसाधारण को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने में सहकारिता का अहम योगदान

35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने का प्रावधान

768 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय होंगे

200 करोड़ रुपये का सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणों हेतु बजट

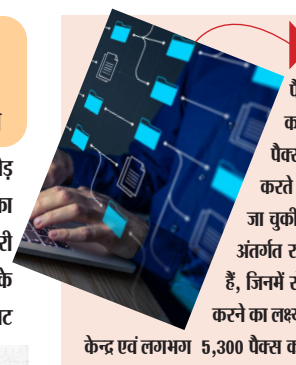

दिनेश शर्मा
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता हमारे सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन भारतीय लोकाचार में भी सहकारिता के बीज देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद जैसे प्राचीन शास्त्र में भी संगठन और सहकारिता पर जोर दिया गया है। वसुधैव कुटुबकम से बड़ा सहकारिता मंत्र और क्या हो सकता है, जिसमें कुछ लाख या करोड़ लोगों के बीच नहीं, मानव मात्र के बीच नहीं, सपूर्ण प्रकृति जिसमें मूर्त और अमूर्त, चल और अचल, सभी के बीच, अनंत, शाश्वत और सनातन पारस्परिक निर्भरता और सहअस्तित्व की संकल्पना है। समय के साथ सहकारी आन्दोलन मजबूत हुआ और इसने सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से किसानों, श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु व्यवसाईयों एवं विविध स्तरों पर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न जनसाधारण को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने में सहकारिता का अहम योगदान है। सहकारिता के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। पूरा विश्व 'सहकारिता से एक बेहतर दुनिया का निर्माण होता है' थीम पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहा है। राजस्थान में भी सहकारी आन्दोलन का लगभग 125 वर्षों का गौरवशाली इतिहास है। राजस्थान में वर्ष 1904 में अजमेर से सहकारी आन्दोलन की शुरूआत हुई और वर्तमान में इसने विशाल वट वृक्ष का रूप ले लिया है। वर्तमान में राज्य में 41 हजार से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियों के 1 करोड़ 10 लाख से अधिक सदस्य हैं। सहकारिता के महत्व को इंगित करते हुए 6 जुलाई, 2021 को केन्द्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर श्री अमित शाह को इसका जिमा सौंपा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना पर मंत्रालय द्वारा 'सहकार से समृद्धि' योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 60 से अधिक पहलों के माध्यम से सहकारी सेक्टर को सशक्त बनाया जा रहा है। ये पहलें विशेष रूप से सहकारी समितियों, किसानों, कारीगरों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में केन्द्रित हैं। राज्य में योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य शीर्ष समिति गठित है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सहकारी विकास समिति एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति गठित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक के निर्देशन में राजस्थान भी 'सहकार से समृद्धि' के पथ पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है। 'सहकार से समृद्धि' की विभिन्न पहलों को क्रियान्वित करने एवं सहकारी क्षेत्र में नवाचार करने में राज्य अग्रिम पंक्ति में है। सहकारिता हमारी सामाजिक परपरा के साथ ही हमारी आवश्यकता भी है। बदलते दौर में यह और अधिक प्रासंगिक होती जा रही है। यह आर्थिक सशक्तीकरण के साथ ही ग्रामीण विकास में योगदान देती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। सहकारी संस्थाएं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं, जिससे पलायन रूकता है। सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता एवं नेतृत्व के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सहकारिता जाति, वर्ग, धर्म और लिंग आदि से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलती है, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। आशा है कि राज्य व केन्द्र सरकार और अन्य स्टेकहोल्डर्स मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में राज्य में सहकारिता आन्दोलन को नई दिशा देकर विकसित राजस्थान के संकल्प का साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगें।

5,300 से अधिक पैक्स गो-लाइव

पैक्स कप्यूटराइजेशन के अंतर्गत अब तक 5,300 से अधिक पैक्स को गो-लाइव किया जा चुका है। प्रत्येक पंचायत में बहुउद्देशीय पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य सहकारी समितियों के गठन की दिशा में कार्य करते हुए अब तक लगभग 2,700 नई सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं। विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत राज्य में 500 मीट्रिक टन के 135 गोदाम स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनमें से 97 गोदामों का निर्माण आगामी जुलाई माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य की 3,800 से अधिक पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र एवं लगभग 5,300 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य कर रही हैं। सहकारी क्षेत्र में प्रदेश की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा 'को-ऑप राइड' का विगत दिनों उदयपुर से शुभारभ हुआ है।

को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के मान-सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के राज्य के पात्र किसानों को अब 9,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं। राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 12 हजार रुपये करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत गोपालक परिवारों को गाय/भैंस के लिए शैड, खेली निर्माण और चारा/बांटा सहित उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नवीन को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिले की 231 पैक्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम

सहकारी समितियों पर आयोजित किए जाएंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले की 231 ग्राम सेवा सहकारी समितियां यथा पैक्स में संचालक मंडल सहित 50 किसान सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में सीसीबी प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण ने एक पत्र जारी किया हैं । जिसके मुताबिक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को आयोजित बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाएं जा रहें हैं, जिसका उद्देश्य पैक्स कम्प्यूटरीकरण और अन्य सुधारों सहित गतिविधियों के विस्तार को कवर करना है, क्योंकि क्स की दक्षता और व्यवसाय वृद्धि से उच्च स्तरीय संस्थाओं (राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक) को व्यवसाय वृद्धि और अन्य पहलुओं में लाभ होगा। वही पत्रानुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम समिति मुख्यालय पर या समिति के पास कार्यालय नहीं होने की स्थित में ग्राम पंचायत भवन पर प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय भार ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर से ही वहन किया जाएगा। वही प्रशिक्षण के उपरांत समस्त दस्तावेजों की एक प्रति शाखा को प्रस्तुत करने होगी तथा उसके आधार पर शाखा प्रबंधक की ओर से प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर बनाकर सीसीबी प्रधान कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं ।

प्रशिक्षण में दी जाएगी प्रमुख गतिविधियां की जानकारी

जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषकर पैक्स के कम्प्यूटरीकरण और दक्षता सुधार पर संक्षिप्त परिचय देने के उपरांत पैक्स कम्प्यूटरीकरण से होने वाले लाभों यथा दक्षता में वृद्धि, पारदर्शिता, डेटा प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी । साथ ही, पैक्स में उपयोग किए जाने वाले संभावित सॉफ्टवेयर-एप्लीकेशन का परिचय और उसकी कार्यप्रणाली का अवलोकन किया जाएगा । इसके अलावा, पैक्स में व्यवसाय विस्तार और विविधीकरण की विभिन्न गतिविधियों यथा कृषि ऋण, फसल बीमा, कॉमन सर्विस सेन्टर, जन औषधि केन्द्र, गोदाम उपयोगिता खाद-बीज वितरण, कस्टम हायरिंग केन्द्र एवं अन्य ऋण पर चर्चा की जाएगी । अंत में प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया भी ली जाएगी

---

20 जीर्ण-शीर्ण गोदामों वाली सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का होगा पुनर्निर्माण

सहकारिता विभाग ने 42 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए जारी की स्वीकृति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य की 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं 5 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 250 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण होगा । साथ ही, 20 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जीर्ण-शीर्ण गोदामों का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा । इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं । जिसके मुताबिक, अजमेर जिले की अराई केवीएसएस, अलवर जिले की अलवर केवीएसएस, बीकानेर जिले की श्रीडूंगरगढ केवीएसएस, बांसवाडा जिले की बांसवाडा केवीएसएस तथा बूंदी जिले की श्री केशव केवीएसएस में 250 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण होगा । इसी प्रकार, अजमेर जिले की नरवर, सीकर की पेवा, श्यामपुरा, जयपुर की सिंगोदकला, भट्टो की गली, चुरू की बैरासर छोटा, सोमसीसर, भरतपुर की सुहारी, सवाईमाधोपुर की खेडा का बाढ रामगढ, टोंक की आमली, पाली की सेवरिया, जालौर की थूर, चित्तौड़गढ़ की बलकुंडीकला, गोपालपुरा, प्रतापगढ़ जिले की उठेल, राजसमन्द की काकरोंद, झालवाड़ की बांवडीखेडा जीएसएस में 250 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए प्रति समिति 16 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी ।

20 जीर्ण-शीर्ण गोदामों का होगा पुर्ननिर्माण

सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की पालना में 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का पुनर्निर्माण करवाया जाना है। जिसके क्र म में बीकानेर जिले की खारिचारनान, उदारासर, झुझुंनू की लाम्बा, भूकान, जयपुर की इटावा भोपजी, श्यामियों की ढाणी, डीग की दांतलौटी, सुपावस, टोंक की आंटोली, धौली, बहड़, तुर्किया, चंदवाड़, जूनिया, बाड़मेर की नेतराड़, सिरोही की जावाल, बांसवाड़ा की बोरवट, चित्तौड़गढ़ की जवाहरनगर, कोटा की गंगापुर, बारां की गोवर्धनपुरा जीएसएस में 100 मैट्रिक टन गोदाम का पुर्ननिर्माण करवाने के लिए प्रति समिति 12 लाख रुपए व्यय होगे ।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर राजस्थान में सहकार एवं रोजगार उत्सव

(ग्राम दादिया जयपुर, 17 जुलाई को प्रातः 11 बजे)

पर मुख्य अतिथि के रुप में जयपुर पधार रहे

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार

का हार्दिक स्वागत-वंदन-अभिनंदन

हनुमानसिंह राजावत - प्रांतीय अध्यक्ष, देवेन्द्र कुमार सैदावत - महामंत्री, महिपालसिंह दवेला - महासचिव

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन जयपुर

व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों एवं सेल्समैनों का प्रतिनिधी संगठन

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।